देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 11.02.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हरिद्वार–रुड़की महायोजना–2041 के संबंध में समीक्षा बैठक हुई।
- प्रदेश के 16 जर्जर व क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग पांच करोड़ अड़सठ लाख रुपये स्वीकृत।
- चम्पावत जिले में चलाए जा रहे अपना स्कूल–अपनी ज़मीन अभियान में आई तेजी।
- अल्मोड़ा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिले के 11 विकासखंडों के मास्टर ट्रेनरों के लिए पांच दिवसीय उत्तरा मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

हरिद्वार–रुड़की महायोजना

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में हरिद्वार और रुड़की महायोजना–2041 के संबंध में नगर व ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। बैठक में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार–रुड़की महायोजना का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए महायोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, जिससे क्षेत्र के नियोजित व सतत विकास को नई गति मिल सके। गौरतलब है कि इस महायोजना के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। इसके तहत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 और रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव व आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों और सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता और नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके।

विद्यालय पुनर्निर्माण

प्रदेश सरकार ने राज्य के 16 जर्जर व क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग पांच करोड़ अड़सठ लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके तहत रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली और देहरादून जिलों के विद्यालयों के भवनों का निर्माण और मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग और पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय में सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

डिजिटल शैक्षिक पहल

बोर्ड परीक्षार्थियों को कठिन विषयों की सरल तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरिद्वार जिले में संचालित डिजिटल शैक्षिक पहल ज्ञान गंगा के तहत विद्यार्थियों के लिए सुगम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कठिन विषयों को सरल रूप में प्रस्तुत करना समय की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सऐप, फेसबुक और अन्य डिजिटल माध्यमों से शैक्षिक वीडियो का प्रसार, विद्यार्थियों तक समान रूप से ज्ञान पहुंचाने में सहायक है।

अपना स्कूल अपनी जमीन

चम्पावत जिले में सरकारी स्कूलों की भूमि को अतिक्रमण और कानूनी विवादों से बचाने के लिए चलाए जा रहे अपना स्कूल–अपनी ज़मीन अभियान ने गति पकड़ ली है। अभियान के तहत अब तक 117 विद्यालयों की भूमि का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 193 अन्य विद्यालयों में यह प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के अनुसार, अभियान शुरू होने से पहले जिले में केवल 55 स्कूलों की भूमि के दस्तावेज स्पष्ट थे। अब प्रशासन और शिक्षा विभाग के समन्वय से इस संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के विद्यालयों में राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजस्व और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस पहल को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया।

कार्यशाला

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिले के 11 विकासखंडों के मास्टर ट्रेनरों के लिए पांच दिवसीय उत्तरा मॉड्यूल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह कार्यशाला शुरू की गई है। कार्यशाला के समन्वयक रमेश रावत ने बताया कि कार्यशाला में 12 मास्टर ट्रेनर और हवालबाग विकासखंड की 20 आंगन बाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य उत्तरा मॉड्यूल के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है।

बाल विकास विभाग, हवालबाग विकासखंड की सुपर वाइजर करुणा टम्टा ने कहा कि उत्तरा मॉड्यूल कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययन कर रहे बच्चों में शिक्षा के प्रति परिवर्तन आएगा।

निरीक्षण

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कार्मिकों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज, सहकारिता, समाज कल्याण, पशुपालन और महिला एवं बाल विकास विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही स्वच्छता, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।